



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 908]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 17, 2014/चैत्र 27, 1936

No. 908]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 17, 2014/CHAITRA 27, 1936

कोयला मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2014

**का.आ. 1103(अ).**—कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 9 की उप-धारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड(ii), तारीख 14 अप्रैल, 2012 में प्रकाशित भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 1336, तारीख 10 अप्रैल, 2012 के प्रकाशन पर, उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित भूमि (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त भूमि कहा गया है) में या उस पर के सभी अधिकार, उक्त अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, आत्यंतिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो गए हैं।

और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है, कि ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, संकतोड़िया, डाकघर दिशेशगढ़, जिला बर्द्धवान (पश्चिमी बंगाल) (जिसे इसमें इसके पश्चात् सरकारी कंपनी कहा गया है), ऐसे निबंधनों और शर्तों का, जिन्हें केन्द्रीय सरकार इस निमित्त अधिरोपित करना उचित समझे, अनुपालन करने के लिए रजामंद है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि उक्त भूमि में और उस पर के इस प्रकार निहित उक्त भूमि में या उस पर के सभी अधिकार, तारीख 14 अप्रैल, 2012 से केन्द्रीय सरकार में इस प्रकार निहित बने रहने के बजाए, निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए सरकारी कंपनी में निहित हो जाएंगे, अर्थात् :-

- (1) सरकारी कंपनी, उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन यथा अवधारित प्रतिकर, ब्याज, नुकसानियों और वैसी ही मदों की बाबत किए गए सभी संदायों की केन्द्रीय सरकार को प्रतिपूर्ति करेगी;
- (2) शर्त (1) के अधीन, सरकारी कंपनी द्वारा केन्द्रीय सरकार को संदेय रकमों का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए उक्त अधिनियम की धारा 14 के अधीन एक अधिकरण का गठन किया जाएगा तथा ऐसे किसी अधिकरण और उक्त अधिकरण की सहायता करने के लिए नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में उपगत सभी व्यय,

सरकारी कंपनी द्वारा वहन किए जाएंगे और इस प्रकार निहित उक्त भूमि में या उस पर के सभी अधिकारों के लिए या उनके संबंध में अपील आदि, जैसी सभी विधिक कार्यवाहियों की बाबत उपगत, सभी व्यय, सरकारी कंपनी द्वारा वहन किए जाएंगे;

- (3) सरकारी कंपनी, केन्द्रीय सरकार या उसके पदधारियों की, ऐसे किसी अन्य व्यय के संबंध में क्षतिपूर्ति करेगी जो इस प्रकार निहित उक्त भूमि में या उस पर के सभी अधिकारों के बारे में, केन्द्रीय सरकार या उसके पदधारियों द्वारा या उनके विरुद्ध किन्हीं कार्यवाहियों के संबंध में आवश्यक हो;
- (4) सरकारी कंपनी को केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना, उक्त भूमि को और इस प्रकार निहित उक्त भूमि में या उस पर के अधिकारों को किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित करने की शक्ति नहीं होगी; और
- (5) सरकारी कंपनी, ऐसे निदेशों और शर्तों का, पालन करेगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, जब कभी आवश्यक हो, उक्त भूमि के विशिष्ट क्षेत्रों के लिए दिए जाएं या अधिरोपित किए जाएं।

[फा.सं. 43015/03/2010—पीआरआईडब्ल्यू—I]  
विवेक भारद्वाज, संयुक्त सचिव

### MINISTRY OF COAL

#### ORDER

New Delhi, the 7th April, 2014

**S.O. 1103(E).**—Whereas on the publication of the notification of the Government of India in the Ministry of Coal, number S.O.1336, dated the 10th April, 2012, in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 14th April, 2012, issued under sub-section (1) of Section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act), the land and all rights in or over the land described in the Schedule appended to the said notification (hereinafter referred to as the said land) vested absolutely in the Central Government free from all encumbrances under sub-section (1) of Section 10 of the said Act.

And whereas the Central Government is satisfied that the Eastern Coalfields Limited, Sanctoria, Post Office Dishergarh, District Burdwan (West Bengal) (hereinafter referred to as the Government company) is willing to comply with such terms and conditions as the Central Government thinks fit to impose in this behalf.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the said Act, the Central Government hereby directs that the said land and all rights in or over the said land so vested shall, with effect from the 14th April, 2012, instead of continuing to so vest in the Central Government, vest in the Government company, subject to the following terms and conditions, namely :—

- (1) the Government company shall reimburse to the Central Government all payments made in respect of compensation, interest, damages and the like, as determined under the provisions of the said Act;
- (2) a Tribunal shall be constituted under Section 14 of the said Act, for the purpose of determining the amounts payable to the Central Government by the Government company under condition (1), and all expenditure incurred in connection with any such Tribunal and persons appointed to assist the said Tribunal shall be borne by the Government company and similarly, all expenditure incurred in respect of all legal proceedings like appeals etc., for or in connection with the rights, in or over the said land, so vested, shall also be borne by the Government company;
- (3) The Government company shall indemnify the Central Government or its officials against any others expenditure that may be necessary in connection with any proceedings by or against the Central Government or its officials, regarding the rights in or over the said land so vested;
- (4) The Government company shall have no power to transfer the said land and the rights in or over the said land so vested to any other person without the prior approval of the Central Government; and
- (5) The Government company shall abide by such directions and conditions as may be given or imposed by the Central Government for particular areas of the said land, as and when necessary.

[ F. No. 43015/03/2010-PRIW-I]

VIVEK BHARADWAJ, Jt. Secy.